



ग्रुप-5 समाचार



लखनऊ ॥ शुक्रवार ॥ 4 अप्रैल, 2025

वर्ष: 17 ॥ अंक: 105 ॥ पृष्ठ: 12 ॥ मूल्य: 2/-

अंदर पढ़ें ॥ 08 आज मुंबई और लखनऊ के बीच मैच में रोहित और पंत ॥ 07 13 साल में बना दिया करोड़ों का ब्रांड ॥ 11 कांचा गांधीबोवली मामले को लेकर ऋचा चड्ढा

सप्तम मां कालरात्रि



मां के सप्तम रूप का नाम है माँ कालरात्रि। यह मां का अति भयावह व उग्र रूप है। सम्पूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह और कोई दूसरा नहीं। किन्तु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। देवी मां का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है।

बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा हमारी है: जयशंकर

बैकॉक (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी बिमस्टेक में अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और वह आर्थिक और भू-राजनीतिक गतिविधियों से अवगत है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि क्षेत्रीय सहयोग एक एकीकृत दृष्टिकोण है न कि चुनिंदा विषयों पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे लंबी तटरेखा



है। उनका यह बयान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया और नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुस के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने चीन के दौरे पर कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर के सात राज्य स्थलबद्ध (लैंड लॉक्ड) हैं, इसलिए बंगाल की खाड़ी और सटे हिन्द महासागर का वह अकेला संरक्षक है। माना जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का नवीनतम बयान कि बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे लंबी तटरेखा भारत की है, मोहम्मद युनुस पर एक तरह का अप्रत्यक्ष कटाक्ष है। युनुस के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया था।

जानलेवा होती जा रही हैं भारत की पटाखा फैक्ट्रियां

नई दिल्ली (एजेंसी)। इस साल भारत में पटाखा फैक्ट्रियों में हुए हादसों के चलते लगभग 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन हादसों की सबसे बड़ी वजह नियमों का पालन नहीं होना है। मंगलवार एक अप्रैल को गुजरात की एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक, धमाका इतना भयानक था कि कई मृतकों के शरीर के



अंग 200-300 मीटर दूर एक खेत में बिखरे हुए मिले। ज्यादातर मृतक मध्यप्रदेश के हरदा और देवास जिले के रहने वाले थे। एक हादसा पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में भी हुआ। यहां एक पटाखा फैक्ट्री और गोदाम में भीषण आग गई जिसकी चपेट में आने से एक परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चार बच्चे भी शामिल थे। पुलिस ने फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक, इस साल पटाखा फैक्ट्रियों में हुए हादसों के चलते लगभग 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे पहले हरदा में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

गरीब मुसलमानों को न्याय मिले, यही हमारा उद्देश्य

● राज्यसभा में रिजिजू बोले-वक्फ में गैर-मुस्लिमों का दखल नहीं होगा

कांग्रेस ने कहा-यह मुस्लिमों के खिलाफ, पोलराइजेशन के लिए लाए

नई दिल्ली (एजेंसी)। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया, उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया। रिजिजू ने कहा- संशोधित बिल में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। हमने ट्रांसपैरेंसी, अकाउंटैबिलिटी, एक्युरेसी पर केंद्रित बदलाव किए हैं। हम किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। गरीब मुसलमानों को न्याय मिले, हमारा यही उद्देश्य है। रिजिजू ने कहा- दुनिया की सबसे ज्यादा लैंड प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। जब इतनी प्रॉपर्टी है तो मुसलमानों को फायदा क्यों नहीं मिल रहा।



● कांग्रेस बोली-पोलराइजेशन के लिए बिल लाया गया- कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा- इनको 2024 में क्यों याद आया। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मेजॉरिटी नहीं मिली। इसलिए ये पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं। सभी जानते हैं कि देश में कौन धुवीकरण करता है। ये बिल मिसइन्फॉर्मेशन कैपेन पर है। पूरा गोदी मीडिया इसमें लग गया। रिजिजू कह रहे हैं कि गरीब की मदद करेंगे। आप 10 साल से सत्ता में हैं, तब क्यों नहीं किया। बीजेपी शासित राज्यों में वक्फ बोर्ड नहीं बनाए गए, फिर कहते हैं कि ट्रांसपैरेंसी लाएंगे।

हमने ट्रेन, प्लेन में नमाज पढ़ ली तो क्या वो हमारा हो गया

हुसैन ने कहा- बार-बार कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी जमीन डिकलेयर कर सकता है। क्या भारत में कोई कानून नहीं है। अगर हमने ट्रेन, प्लेन में नमाज पढ़ ली तो क्या ट्रेन-प्लेन हमारा हो गया। उन्होंने कहा- अगर वक्फ बोर्ड के सामने कोई शिकायत आती है तो हम जांच करते हैं। मैं 6 साल से कर्नाटक वक्फ बोर्ड में हूँ। कोई शिकायत आने पर कई स्तरों पर जांच होती है। आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि पहले ट्रिब्यूनल के अलावा अपील नहीं कर सकते थे। नसीर ने आगे कहा- वक्फ के मायने दान हैं। ये कोई भी कर सकता है।

अदालत का सम्मान, पर फैसला स्वीकार नहीं

● 26 हजार भर्ती खारिज होने पर ममता बनर्जी के सख्त तेवर



मध्य प्रदेश के व्यापम केस में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कौन-कौन जेल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि 26

अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तो ममता का इस्तीफा ही मांग लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदार सीएम ममता बनर्जी रही

हजार अध्यापकों और अन्य स्टाफ की भर्ती में गड़बड़ियां हुई हैं और यह दागी प्रक्रिया रही। इसलिए इस भर्ती को रद्द किया जाता है। अब इस मामले पर भाजपा ने ममता पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और बंगाल भाजपा के

हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी के शासन में मेरिटधारी युवाओं के साथ धोंधली की गई है। ऐसा पैसों के बदले हुआ है। पैसों के बदले में फर्जी भर्ती कर ली गई है।' इसके आगे उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी ने न सिर्फ योग्य उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी की है बल्कि उनके परिवारों को भी धोखा दिया है। टीएमसी की सांसद डोला सेन ने कहा कि पार्टी अदालत के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन यह भी सच है कि हमने करप्शन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस मामले की जांच करेगी। हम इस मामले में कानूनी राय लेने के बाद जवाब देंगे। पार्टी हमेशा अच्छे उम्मीदवारों के साथ खड़ी रहेगी।

अब शिंदे के पास जाएगी हर फाइल

अजित पवार से ज्यादा

हुई पावर

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र सरकार में बीते कई महीनों से चली आ रही खींचतान अब खत्म होती दिख रही है। पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गई तो



वह होम मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन वह भी नहीं मिला तो कुछ मंत्रालय लेकर डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद भी उनकी नाराजगी बनी ही रही। कभी प्रभारी मंत्रियों को लेकर तो कभी मंत्रालयों के फैसलों को लेकर वह खफा दिखते थे। एक मलाल यह भी रहा कि अजित पवार को उनसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस सरकार में उनका कद बढ़ा दिया गया है। अब महाराष्ट्र सरकार के कामकाज की कोई भी फाइल उनसे होकर ही सीएम देवेंद्र फडणवीस तक जाएगी।



CBSB BOARD

ADMISSION OPEN

PLAYGROUP TO IX & XI

ABOUT US

- Co-Educational
- Highly Qualified + Experienced Teachers
- Smart Classes
- Remedial Classes
- Summer Camp
- 24X7 Under Surveillance
- Conductive Learning Environment
- Well Equipped Library
- Well Equipped Physics
- Chemistry & Bio Lab
- Expert Career Counselling Sessions
- Intensive Skill Acquisition

BENEFITS

- Scholarships for
- Meritorious Students
- Scholarships for
- Single Girl Child
- Siblings Discount
- Early Bird Discount
- Free School Bags to
- New Admission
- Free School Diary

TRANSPORT FACILITY AVAILABLE

www.rasphilacademy.com

7398323893, 9198392082

Kanchana Bihari Marg, Adil Nagar Lucknow, Uttar Pradesh 226022

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए आबकारी विभाग के 46 प्रोजेक्ट तैयार, 7,588 करोड़ का होगा इन्वेस्टमेंट, मिलेगा 10,957 लोगों को रोजगार : आबकारी मंत्री

ग्रुप 5 संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान आबकारी विभाग की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि सरकार को राजस्व देने में आबकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट्सु किया उससे विभाग के राजस्व में साल दर साल राजस्व के बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बताया कि 2017 में 14 हजार करोड़ राजस्व था. 2024-25 के फाईनेंशियल ईयर खत्म होने तक आबकारी विभाग का राजस्व अब तक सर्वाधिक है. 52,297.08 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले साल 45,570.47 करोड़ रुपए था। पिछले साल से अब तक 6000 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश चाहे शीरा उत्पादन हो, चाहे एथेनॉल का उत्पादन हो, देश में सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर



प्रदेश करता है। 2023-24 में शीरे का उत्पादन 527 लाख कुंतल था जो देश में सर्वाधिक है। एथेनॉल की बात करें पिछले वित्तीय वर्ष में 176 करोड़ लीटर हुआ है। हमारा लक्ष्य 200 करोड़ लीटर तक उत्पादन पहुंचाएं। आबकारी मंत्री ने कहा कि अभी हमारी लॉटरी का समापन हुआ है। मुझे खुशी है यह बताते हुए कि हमारी लॉटरी के दो चरण संपन्न हो चुके हैं। तीसरा चरण शुरू है। हम 99.97 प्रतिशत काम कर चुके हैं। पहले विदेशी मदिरा और अलग-अलग बियर की दुकान होती थीं अब एक

हैं। इन्वेस्टर समिट में आबकारी विभाग को 137 एमओयू हुए थे। 39708 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए हमारे पास 46 प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हैं। उनसे 7588 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 10957 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में अब तक 10,184 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। हमारा सबसे ज्यादा फोकस प्रवर्तन कार्रवाई पर रहता है। पिछले तीन वर्षों में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है।

इस बार लॉटरी में 40 प्रतिशत नए कारोबारियों को आने का मौका मिला : नितिन अग्रवाल

आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में अन्य प्रदेशों से कोई अवैध मदिरा न आने पाए जो कच्ची शराब बनाने का अवैध कार्य करते हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो इसके लिए हम प्रयास करते हैं। इस बार लॉटरी में 4० प्रतिशत नए कारोबारियों को आने का मौका मिला है। जहां शराब बनती है और जहां विकती है उस पूरे सिस्टम को हमने ऑनलाइन जोड़ दिया है, इससे पारदर्शिता आई है। हमने विभाग की सारी पत्रावलियों को ऑनलाइन किया है। सभी यूनिटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। हमने वाहनों में जीपीएस लगाए जिससे कहीं किसी लोकेशन पर जाना है तो उस डिस्टेंस में कितना समय लगेगा इसकी पूरी जानकारी हमें मिलेगी। हमने परमिट ऑनलाइन किया है। विभाग ने अपने को पूरी तरह से डिजिटाइज किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का जो हमारा लक्ष्य 6३000 करोड़ रुपए का है। राजस्व का जो पैसा पहले माफिया की जेब में जाता था उससे आबकारी विभाग को चलाया जाता था। हमने उस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब राजस्व का पैसा प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए काम में आता है। कुल राजस्व का 40 प्रतिशत देसी मदिरा से तो 60 प्रतिशत वाइन और बीयर से आता है।

किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हमने इंफोसमेंट टीम को मजबूत किया है। लगातार कार्रवाई बढ़ाई है। इस बार एनफोर्समेंट में नई व्यवस्था लागू की है। पूरे प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया है। नौ नौ मंडलों के दो पार्ट बनाए हैं। पश्चिमी

और पूर्वी उत्तर प्रदेश को अलग किया है। दो संयुक्त आबकारी आयुक्त को जिम्मेदारी दी है कि प्रवर्तन कार्रवाई को और भी मजबूत किया जाए। एक लाख 12 हजार 279 अभियोग पंजीकृत किए हैं। 24 हजार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।



संचालन न करें। नाबालिंग के ई रिक्शा का संचालन मिलने पर या ई रिक्शा के वैध लाइसेंस के बिना संचालन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। चालकों को इस संबंध में जागरूक भी किया जाए। परिवहन मंत्री ने बताया कि लखनऊ संभाग में कुल 280 ई रिक्शा का चालान किया गया और 86 ई रिक्शा को सीज किया गया। गाजियाबाद संभाग में

280 चालान और 86 सीज, झांसी संभाग में 208 चालान व 36 सीज, आगरा संभाग में 264 चालान व 76 सीज, वाराणसी संभाग में 114 चालान और 27 सीज, मुरादाबाद संभाग में 310 चालान व 42 ई रिक्शा सीज किये गये। उन्होंने बताया कि कुल तीन दिन की कार्रवाई में 2751 ई रिक्शा सीज किये गये और 9022 ई रिक्शा का चालान किया गया।

तीन दिन की कार्रवाई में ही पर्त हुए अवैध ई-रिक्शा चालक

2751 ई-रिक्शा सीज, 9022 का चालान

ग्रुप 5 संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ई रिक्शा के अवैध संचालन पर रोक लगाने के लिए प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। अभियान के तीसरे दिन गुरुवार को प्रदेश भर में प्रवर्तन दल ने कुल 829 ई रिक्शा सीज किए गए और 2894 ई रिक्शा का चालान किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे ई रिक्शा जो बिना पंजीकरण सड़क पर दौड़ रहे हैं, बिना फिटनेस या बिना कागजात पूरे किये ही संचालित हो रहे हैं, के खिलाफ परिवहन विभाग का अभियान जारी है। मुख्यमंत्री ने सवारियों को सुरक्षित सफर कराने के साथ ही शहर को जाम मुक्त कराने के लिए अवैध तरीके से संचालित ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने प्रवर्तन



दल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जांच अभियान की कार्रवाई में और तेजी लाएं, जिससे अनाधिकृत ई रिक्शा का संचालन रोक जा सके, साथ ही उन्होंने पुलिस और यातायात विभाग के अधिकारियों से भी इस कार्य में सहयोग करने के निर्देश दिये। उन्होंने सख्त निर्देश दिये कि प्रवर्तन दल सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में नाबालिंग ई रिक्शा का

लोकबन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय का राष्ट्रीय असेसर टीम ने किया निरीक्षण



लखनऊ, (ग्रुप 5 सं.)। लोकबन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय में स्वास्थ्य गुणवत्ता आश्वासन एवं मुस्कान राष्ट्रीय प्रमाणन के तहत भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय असेसर टीम ने तीन दिवसीय निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के 16 प्रमुख विभागों का गहन मूल्यांकन किया गया। निरीक्षण के पहले दिन इमरजेंसी, सीएनसीयू, पीडियाट्रिक वार्ड, लेबर रूम और गायनी ओटी का विशेष रूप से मूल्यांकन किया गया, क्योंकि ये संवेदनशील विभाग माने जाते हैं। तीनों दिन सभी विभागों का विस्तार से निरीक्षण किया गया। बताते कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ मुस्कान कार्यक्रम का उद्देश्य 12 वर्ष तक के बच्चों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर देखभाल प्रदान करना

है। इस कार्यक्रम के तहत नवजात एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाने और रोकथाम योग्य बाल रोगों को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय शंकर त्रिपाठी ने पूरे निरीक्षण के दौरान विभागों का मार्गदर्शन किया, इस दौरान अस्पताल के समस्त चिकित्सक व कर्मचारी उपस्थित रहे। असेसर टीम, जिसमें हिसार (हरियाणा), नई दिल्ली और भोपाल (मध्य प्रदेश) से आए विशेषज्ञों ने अस्पताल में लागू की गई गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि अस्पताल द्वारा किए गए व्यापक प्रयास सराहनीय हैं और इससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रमहक निदेशक डॉ राजेश कुमार ने सभी को धन्यवाद दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री नहीं मिले तो कार्यकर्ता ने कुर्ते में लगाई आग

लखनऊ, (ग्रुप 5 सं.)। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं मिले तो कार्यकर्ता ने कुर्ते में आग लगाई, पीड़ित ने बताया कि लखनऊ में 3 महीने से नेता से मिलने नहीं दिया, राजनीति से संन्यास ले लिया है। पीड़ित ने कहा कि पिछले करीब 3 महीने से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रहा हूं। कई नेताओं से मिलवाने का समय मांगा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। जब अपने नेता से ही नहीं मिल सकता तो पार्टी में रहकर क्या करूंगा। यह कहना है ठाकुरगंज इलाके के रहने वाले सपा नेता नवीन धवन उर्फ बंटी का। बंटी ने 31 मार्च को अपने खादी कुर्ते में आग लगाकर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा- बीते 27 सालों से समाजवादी पार्टी में सक्रिय हूं। इसके बाद भी मुझे अपने नेता से नहीं मिलने दिया जा रहा है। उधर पुलिस ने कहा है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। कुर्ते में आग लगने या लगाने की कोई शिकायत उनके पास नहीं आयी है।

लोकबंधु अस्पताल की नई निदेशक बनी संगीता गुप्ता

लखनऊ, (ग्रुप 5 सं.)। निदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ में तैनात डॉ. संगीता गुप्ता को लखनऊ के लोक बंधु श्री राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय का निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक बनाया गया है।

एलएसजी के खिलाड़ियों ने की लखनऊ मेट्रो में यात्रा

ग्रुप 5 संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटॉर जहीर खान के नेतृत्व में एलएसजी की टीम गुरुवार को

खूबसूरती पर हुए मंत्रमुग्ध

लखनऊ मेट्रो पहुंची। टीम के लिए हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर मीट एंड ग्रीट सेशन आयोजित किया गया। यहां उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने एलएसजी टीम के सदस्यों का गर्म जोशी से स्वागत किया। इस दौरान पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और अपनी स्विंग के लिए मशहूर जहीर खान ने 'एलएसजी रेल' को फीला काट कर रवाना किया। एलएसजी रेल को विशेष रूप से एलएसजी के आर्ट वर्क से सजाया गया था। लखनऊ मेट्रो ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम से करीब



15 क्रिकेट छात्रों को हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर एलएसजी के मेंटॉर जहीर खान, टीम के युवा बल्लेबाज आयुष बड़ोनी, मैथ्यू ब्रोडबैंक और तेजतर्रार ऑल राउंडर अब्दुल समद से मिलवाया। बच्चों ने इस मंच का लाभ उठाते हुए क्रिकेट और उससे जुड़े सवालों को एलएसजी खिलाड़ियों के सामने रख अपनी मन की जिज्ञासा की शांत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जहीर खान ने कहा कि लखनऊ मेट्रो के स्टेशन और ट्रेनें काफी

सुंदर और स्वच्छ हैं। जहीर ने लखनऊ मेट्रो की तरफ से मैच के दिनों में ऑफ़प्रेसन टाइमिंग बढ़ाए जाने की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आधी रात को चलने वाली विशेष ट्रेनों के साथ हमारा परिवहन साझेदार होने के लिए हम लखनऊ मेट्रो के आभारी हैं। हमारी साझेदारी बहुत रणनीतिक है। लखनऊ मेट्रो की तरफ से हजरतगंज से केडी सिंह मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो यात्रा भी आयोजित की गई। केडी सिंह स्टेडियम के युवा खिलाड़ियों ने एलएसजी टीम

डिजिटल हो रहे रेल यात्री, काउंटरों से बना रहे दूरी



एटीवीएन और यूपीआई का कर रहे भरपूर इस्तेमाल, अब काउंटर पर कैश न लेने की योजना बना रहा रेलवे

ग्रुप 5 संवाददाता

लखनऊ। डिजिटल युग में अब रेल यात्री भी काउंटर पर कैश के बजाय स्टेशनों पर टिकट बुकिंग के लिए डिजिटल पेमेंट मिला था, वहीं इस साल लखनऊ डिजिजन को ऑनलाइन पेमेंट के रूप में 34.96 करोड़ रुपए की भुगतान प्राप्त हुआ है। इससे अब रेलवे के अधिकारियों को महसूस होने लगा है कि हर वर्ग के लोग अब डिजिटल पेमेंट करने में सहूलियत महसूस कर रहे हैं। खासकर युवा वर्ग कैश देकर टिकट बुकिंग नहीं करता बल्कि डिजिटल पेमेंट करने में विश्वास रखने लगा है।

248 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी रेलवे की अर्निंग

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की बात की जाए तो अनरिजर्व्ड सेगमेंट में डिजिटल अर्निंग 248.20 प्रतिशत का जबदस्त इजाफा हुआ है। पिछले साल जहां टिकटों की बुकिंग में रेलवे को 1०.04 करोड़ रुपए का डिजिटल पेमेंट मिला था, वहीं इस साल लखनऊ डिजिजन को ऑनलाइन पेमेंट के रूप में 34.96 करोड़ रुपए की भुगतान प्राप्त हुआ है। इससे अब रेलवे के अधिकारियों को महसूस होने लगा है कि हर वर्ग के लोग अब डिजिटल पेमेंट करने में सहूलियत महसूस कर रहे हैं। खासकर युवा वर्ग कैश देकर टिकट बुकिंग नहीं करता बल्कि डिजिटल पेमेंट करने में विश्वास रखने लगा है।

रेलवे ने जारी किया एटीवीएम से टिकट का आंकड़ा

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की तरफ से रेलवे स्टेशनों पर लगी एटीवीएम का एक अप्रैल 2024 से लेकर 28 मार्च 2025 तक का टिकट बुकिंग का आंकड़ा जारी किया गया है। यहां पर टिकट बुक करने के लिए यात्रियों ने काउंटर पर जाने के बजाय इन मशीनों का सहारा लिया। अयोध्या स्टेशन पर 64 प्रतिशत टिकट, अयोध्या कैंट स्टेशन पर 61 प्रतिशत टिकट, अकबरपुर स्टेशन पर 61 प्रतिशत टिकट, लखनऊ स्टेशन पर 64। प्रतिशत और प्रयागराज जंक्शन पर 64। प्रतिशत टिकट एटीवीएम से बुक किए गए।

(एटीवीएम) के साथ ही यूपीआई का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक साल पहले जहां लखनऊ डिबीजन

यह योजना है कि जहां-जहां हमारे काउंटर हैं उन पर कैश देकर टिकट लेने की व्यवस्था ही खत्म करना है।



की सविदा के आधार पर रुपया 40000 प्रतिमाह पर सीधे भर्ती का प्लान बनाकर आदेश जारी कर दिया। एक तरफ पावर कॉरपोरेशन घाटे की बात कहकर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से भर्ती किए गए फोल्ड में तैनात सविदा कार्मिकों की छंटनी कर रहा है, दूसरी तरफ सीधे सविदा भर्ती का प्लान बना रहा है। ऐसी भर्ती को मास्टर रोल कहा जाता था और बाद में विधिक विवाद के चलते सभी मास्टर रोल को परमानेंट करना पड़ा था। उपभोक्ता परिषद पहले ही पावर कारपोरेशन में लैटरल एंट्री व इस प्रकार की सीधी भर्ती की सीबीआई जांच करने की मांग कर चुका है. उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि पावर कारपोरेशन की इस प्रकार की कार्रवाई

यूपीपीसीएल के ऐप से करें बिजली बिल का भुगतान, अगले माह से राह होगी और आसान

लखनऊ, (ग्रुप 5 संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की डिजिटल भारत को बढ़ावा देने की पहल के तहत उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने मोबाइल ऐप के माध्यम

वेबसाइट पर पहले से लागू, ऐप्स में भी नई व्यवस्था

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बताया कि यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे विभिन्न मोबाइल ऐप्स पर भी लागू कर दिया गया है। वर्तमान में उपभोक्ताओं के लिए पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं जिससे वे नई प्रक्रिया को आसानी से अपना सकें।

से बिजली बिल भुगतान की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल के भुगतान के लिए डिस्कॉम के स्थान पर यूपीपीसीएल और अपने जिले का नाम चयन करना होगा।

अब सिर्फ यूपीपीसीएल और जिले का चयन आवश्यक

भीम ऐप, गूगल पे, फोनपे, पेटीएम और अमेज़न पे जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बिल भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को अब सिर्फ यूपीपीसीएल और अपने जिले का नाम चुनना होगा। इसके बाद उपभोक्ता को अपनी खाता संख्या दर्ज करनी होगी। पहले उपभोक्ताओं को डिस्कॉम का चयन करना पड़ता था, जिसमें गलती की संभावना बनी रहती थी। गलत डिस्कॉम भरने से भुगतान में परेशानी होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए यूपीपीसीएल ने यह बदलाव किया है।

अगले माह से पूरी तरह लागू होगी नई व्यवस्था

यूपीपीसीएल की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अगले माह से केवल नई व्यवस्था ही मान्य होगी। इससे उपभोक्ताओं को भुगतान में और अधिक सहूलियत मिलेगी।

क्या कहते हैं उत्तर रेलवे के डीआरएम

उत्तर रेलवे के डीआरएम सचिंद्र मोहन शर्मा का कहना है कि डिजिटल पेमेंट इस बार काफी बढ़ी हैं जो पिछले साल करीब 1० करोड़ की अर्निंग थी वह 34 करोड़ की है। मुझे लगता है कि



जो नई पीढ़ी है वह अब डिजिटल यूपीआई और पीओएस से काफी कंफर्टेबल है। जो हमारे एटीवीएम से टिकट बुकिंग है वो भी काफी बढ़ी है। हमारे कई स्टेशन ऐसे हैं जहां पर एटीवीएम से ही टिकट बुक हो रहे हैं। लोग काउंटर पर नहीं जा रहे हैं. इनमें अकबरपुर, अयोध्या, अयोध्या कैंट, लखनऊ, प्रयाग संगम में करीब प्रतिशत टिकट और बनारस में 48 प्रतिशत टिकट अब एटीवीएम के माध्यम से बुक हो रहे हैं। पब्लिक को अब ईज ऑफ टिकटिंग चाहिए कि वह जाएं और फट से उन्हें टिकट मिल जाए। अब हम ज्यादा से ज्यादा एटीवीएम लगाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रैजिक्शन से ही टिकट बुकिंग हो इस दिशा में भी अब हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। कई काउंटर हैं जहां पर सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट से ही टिकट मिलें इसकी भी प्लानिंग की जा रही है।

बढ़ाई जाएंगी एटीवीएम

स्टेशनों पर रेलवे की तरफ से एटीवीएम लगाई गई हैं। इन मशीनों से टिकट लेने में यात्री सहूलियत महसूस कर रहे हैं। उनके समय की बचत हो रही है। लिहाजा, अब रेलवे के अधिकारी रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन की संख्या बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा यात्री आराम से अनरिजर्व्ड टिकट ले सकें। उन्हें काउंटर की लाइन में न लगना पड़े।

क्यू आर कोड से टिकट बुकिंग हो रही आसान

रेलवे स्टेशनों पर जगह-जगह क्यूआर कोड की व्यवस्था की गई है। अब इसी कर कोड को स्कैन कर यात्री आनन-फानन में टिकट बुक कर ले रहे हैं। ऑनलाइन भुगतान कर उन्हें उनके मोबाइल पर ही टिकट उपलब्ध हो जा रहा है। इससे उनका काफी टाइम बच रहा है और लाइन में भी नहीं लगना पड़ रहा है। अमूमन काउंटर पर एक टिकट बुक करने में चार से पांच मिनट तक का समय लगता है लेकिन मोबाइल पर टिकट बुकिंग में महज कुछ ही मिनट में काम पूरा हो जाता है, इसलिए डिजिटल पेमेंट कर लोग आराम से टिकट बुक करने लगे हैं। इससे रेलवे को भी काफी सहूलियत मिली है।

कैश काउंटर के बजाय डिजिटल काउंटर

उत्तर रेलवे के अधिकारी अब कैश काउंटर बंद कर सिर्फ डिजिटल काउंटर की व्यवस्था करने का प्लान कर रहे हैं। अधिकारी बताते हैं कि जहां-जहां अभी कैश से काउंटर पर टिकट बुक हो रहे हैं वहां पर अब सिर्फ डिजिटल माध्यम से भुगतान करके ही टिकट बुक हों, इस पर विचार किया जा रहा है। उत्तर रेलवे डीआरएम कार्यालय स्थित दो काउंटर में से एक काउंटर पर अब सिर्फ डिजिटल पेमेंट से ही टिकट बुकिंग की तैयारी है। कैश काउंटर पर सिर्फ कैश वाले लोग ही लाइन में लगेंगे जबकि जिन्हें डिजिटल भुगतान कर टिकट बुक कराना है वह डिजिटल काउंटर पर आराम से अपना टिकट ले सकेंगे।

सिर्फ डिजिटल भुगतान ही स्वीकार किया जाएगा। इससे यात्रियों के समय की बचत होगी, साथ ही अलग से कर्मचारी भी नहीं लगाना पड़ेगा। फुटकर पैसे का भी झंझट खत्म हो जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में बड़ी संख्या में प्रवेश लेने पहुंच रहे छात्र

देहरादून, एजेंसी। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज सेलाकुई में नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभिभावक बड़ी संख्या में विद्यालय पहुंचकर अपने बच्चों का प्रवेश करवा रहे हैं। दो दिन में कक्षा नौ में 90 और छह में 30 छात्र प्रवेश ले चुके हैं। विद्यालय प्रशासन के अनुसार केवल कक्षा छह, नौ और 11 में ही प्रवेश दिए जाएंगे। प्रधानाचार्य यशवंत सिंह बर्तवाल ने बताया कि विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए क्षेत्र से बाहर के अभिभावक भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। खासतौर पर कक्षा नौ में प्रवेश के लिए अधिक आवेदन आ रहे हैं, जिसमें अधिकांश छात्र आसपास के निजी विद्यालयों से स्थानांतरित होकर यहां दाखिला ले रहे हैं। विद्यालय प्रशासन ने कक्षा नौ में 250 छात्रों के प्रवेश लेने का निर्णय लिया है। बताया कि कक्षा नौ के लिए तीन सेक्शन बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक सेक्शन में लगभग 75 से 80 छात्र होंगे। बताया कि इस वर्ष विद्यालय की छात्र संख्या एक हजार के पार पहुंचने की संभावना है। विद्यालय प्रशासन इस बढ़ती संख्या के अनुरूप संसाधनों के विस्तार के लिए प्रयासरत है। ताकि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। विद्यालय में सीटों की सीमित उपलब्धता ध्यान में रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया तय की जा रही है।

कबाड़ के गोदाम में लगी आग, 10 पुरानी कार व सामान जलकर राख

देहरादून, एजेंसी। ढकरानी मोड़ स्थित एक कबाड़ी के गोदाम में बुधवार को आग लग गई। सूचना पर डाकपत्थर से अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंचे। अग्निशमनकर्मियों ने आग बुझाना शुरू किया, लेकिन आग का दायरा बढ़ता जा रहा था। सेलाकुई से भी अग्निशमन वाहन बुलाने पड़े। आग से गोदाम में रखे 10 पुरानी कार और वाहनों से निकाले गए पार्ट्स आदि जल गए। करीब तीन घंटे बाद अग्निशमनकर्मियों ने आग पर काबू पाया। सुबह करीब 11.30 बजे ढकरानी मोड़ पर स्थित खलील के कबाड़ के गोदाम में अचानक से आग लग गई। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते गोदाम से आग की बड़ी-बड़ी लपटें और धुएं के गुबार उठने लगे। ग्रामीणों ने स्वयं ही मोर्चा संभाला, लेकिन आग का दायरा बढ़ने लगा। जब ग्रामीण सफल नहीं हुए तो हर्बर्टपुर पुलिस और डाकपत्थर अग्निशमन स्टेशन को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही स्टेशन से एक टीम अग्निशमन वाहन के साथ मौके पर पहुंच गई। इस बीच आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। सेलाकुई अग्निशमन स्टेश से भी वाहन बुलाया गया। तीन वाहनों की मदद से अग्निशमनकर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने वाली टीम में मनोज नेगी, आकाश चौधरी, रविकांत, सुरेश रावत, कल्पना, सनम पंवार, सोहनर सिंह, शिवकुमार, मीनाक्षी रावत, सरस्वती आदि शामिल रहे।

ऊखीमठ के रुद्रपुर गांव में जमीन कब्जाने का आरोप

देहरादून, एजेंसी। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ ब्लॉक में तीर्थ पुरोहितों के गांव रुद्रपुर में गोचर भूमि को लेकर पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत ने ग्रामीणों के साथ प्रेसवार्ता की। उन्होंने 220/33 केवी उप-स्टेशन के निर्माण में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। कहा, ग्रामीणों की पूरी जमीन पिटकूल को दे दी गई है। पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि रुद्रपुर गांव में 1974 में जमीन का एक हिस्सा अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवारों को दिया गया, जबकि शेष भूमि हमेशा गोचर के रूप में ही अंकित रही। आरोप लगाया कि पिटकूल ने 2008 से इस भूमि पर कब्जा करने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी थीं और 2010 में वन विभाग ने इस भूमि को 30 साल की लीज पर पिटकूल को दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिटकूल ने प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों से मिलकर साजिश रची और फर्जी दस्तावेज के आधार पर लीज हासिल की। इसके विरोध में रुद्रपुर के ग्रामीण उच्च न्यायालय का रुख कर चुके हैं और 2021 में उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को इस मामले की सुनवाई का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होनी है। कहा कि 10 मार्च को जब स्थानीय प्रशासन ने पुलिस बल, पिटकूल कर्मचारियों और ठेकेदारों के साथ गोचर भूमि पर कब्जे का प्रयास किया था तब गांव की महिलाओं ने अपनी भूमि बचाने के लिए संघर्ष किया। इस मौके पर गणेश शुक्ला, शैलेंद्र कोटवाल, पंकज शुक्ला, अमित आदि मौजूद रहे।

गौ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, उत्तराखंड और हिमाचल पुलिस ने किया 10 तस्करों को गिरफ्तार

विकासनगर, एजेंसी। उत्तराखंड और हिमाचल सीमा पर हुई गोकशी की घटना का 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया। घटना में शामिल अंतरराज्यीय गौ तस्कर गिरोह को उत्तराखंड और हिमाचल पुलिस से संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया। गिरोह के आठ आरोपियों को देहरादून पुलिस ने सहस्रपुर क्षेत्र और दो आरोपियों को सिरमौर पुलिस ने पुरुवाला सिरमौर से किया गिरफ्तार। घटना की संवेदनशीलता को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने सिरमौर जाकर एसएसपी सिरमौर से मुलाकात की थी। जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए संयुक्त रणनीति बनाई गई। गिरफ्तार सभी आरोपी पूर्व में भी पशु क्रूरता और गोकशी की घटना में जेल जा चुके हैं। घटना के मुताबिक, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर देवपुर नदी किनारे 31 मार्च को 13 गोवंश के अवशेष पड़े होने की विकासनगर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली। पुलिस

साइबर ठगी के तीन मामले, एक करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड, 6 आरोपी गिरफ्तार

देहरादून, एजेंसी। साइबर क्राइम पुलिस टीम ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के दो मामलों और एक अन्य धोखाधड़ी के मामले में दक्षिण भारत के तीन राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु) और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पहले मामले में रुड़की निवासी पीड़िता सेवानिवृत्त महिला बैंक अधिकारी को साइबर ठगों ने उनके पति के बैंक खाते में मनी लॉन्ड्रिंग होने का भय दिखाकर ठगी को अंजाम दिया था। ठगों ने पीड़िता को 24 घंटे से भी अधिक समय तक वीडियो/ऑडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट कर 32 लाख 31 हजार रुपये ठगे थे। जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दूसरे मामले में पीड़िता के मोबाइल नंबर पर अनजान नंबर से एक व्हाट्सएप कॉल आई। जिसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर कहा कि आपके आधार कार्ड से कैनरा बैंक की मुंबई शाखा में एक बैंक खाता खोला गया है। जिसमें 2 करोड़ रुपये की अवैध धनराशि का लेनदेन हुआ है, जो



कि नरेश गोयल नाम के व्यक्ति के मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित है। उसके बाद पीड़िता को उसी व्हाट्सएप नंबर से नरेश गोयल नाम के व्यक्ति का फोटो और गिरफ्तारी वारंट भेजे गए। पीड़िता को वीडियो कॉल पर सीबीआई गिरफ्तारी वारंट, आरबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय का एक नोटिस दिखाया। पीड़िता को 24 घंटे से भी अधिक समय तक वीडियो/ऑडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट कर 23 लाख रुपये की धनराशि ठगे जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था। तीसरे मामले में खुद को

कंपनी का मालिक बताने वाले शख्स के द्वारा एक खाता नंबर बताया गया और अकाउंटेंट को आरटीजीएस के माध्यम से 38 लाख रुपये की धनराशि जमा करने को कहा गया। राशि को जमा करने के बाद दोबारा 15 लाख रुपये की धनराशि जमा करने के लिए कहा गया। यह राशि भी जमा होने के बाद दोबारा 35 लाख रुपये की धनराशि जमा करने के लिए कहा गया। शक होने पर अकाउंटेंट के द्वारा कार कंपनी के स्वामी से घटना का जिक्र किया गया। तब जाकर पता लगा कि वो किसी ठगी का शिकार हो गए हैं। जिस पर तत्काल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के साइबर पुलिस टीम द्वारा मुकदमे की जांच की तो डिजिटल अरेस्ट के पहले मामले में सधुलुरी सिंधु और मुच्चा भार्गव को मल्लमपेट थाना ड्यूटीगल कमिश्नरेट हैदराबाद तेलंगाना और पी मणिकन्दन निवासी पुडुचेरी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई और कब्जे से प्रोजेक्ट में तत्काल कुछ राशि निवेश करनी है। चूंकि घटना के समय कंपनी के मालिक देहरादून से कहीं बाहर गए हुए थे। जिससे अकाउंटेंट को विश्वास हो गया। उसके बाद स्वयं को कार

लैंड फ्रॉड से बचाएगा राज्य का पहला डेडिकेटेड ई कंप्यूटर कियोस्क सचेतक

देहरादून, एजेंसी। भूमि फर्जीवाड़ा रोकने और आमजनता को भूमि खरीदने-बेचने में फर्जीवाड़े से बचाने के लिए राज्य का प्रथम डेडिकेटेड ई-कम्प्यूटर कियोस्क की शुरुआत हो गई है। बुधवार को देहरादून कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के पास बने राज्य के प्रथम डेडिकेटेड ई-कियोस्क 'सचेतक' का उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया है। अब जनता को कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित कियोस्क से निशुल्क और पुख्ता जानकारी मिलेगी। इससे भूमि खरीदने-बेचने से पहले खतौनी, चौहदवी, जियो लोकेशन और भूमि के वास्तविक स्वामी की जांच की सुविधा मिलेगी।

राज्य का पहला डेडिकेटेड ई कंप्यूटर कियोस्क सचेतक लॉन्च- बता दें कि जनता दरबार, बहुउद्देशीय शिविर और अन्य माध्यमों से भूमि धोखाधड़ी की अधिकांश शिकायतें और मामले सामने आ रहे थे। इसका मुख्य कारण भूमि खरीदने वाले लोगों को भूमि के संबंध में पहले से जानकारी नहीं रहना है। खरीददार को पता नहीं होता कि उस भूमि का असली मालिक कौन है। परिसंपत्तियों के रिकॉर्ड के लिए राज्य में एक पोर्टल बना है। इस पोर्टल में भूमि संबंधी पूरी

जानकारी रहती है। आम लोगों को ई-रजिस्ट्रेशन पोर्टल में एक्सेस करने के लिए साधन, सुविधा की कमी रहती है। इसके लिए रजिस्ट्रार और स्टॉप रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की गई। इसके लिए एक डेडिकेटेड कियोस्क तैयार किया गया है। भूमि रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाने से पहले भूमि खरीदने वाले बायर्स निशुल्क इस कियोस्क में भूमि की पुष्टि कर सकते हैं। कियोस्क से भूमि जानकारी मिलेगी। इससे बायर्स समस्याओं पर अंकुश लगेगा। इस ई-कियोस्क का नाम सचेतक रखा गया है। 'सचेतक' ई-कियोस्क के नाम से इसे जनहित में लॉन्च किया गया है। अब संपत्ति खरादने वाली आमजनता को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा। इसका मकसद राजस्व बढ़ाना ही नहीं, बल्कि जनता को धोखाधड़ी से बचना भी है। और ये विभाग की जिम्मेदारी है।

डीएम सविन बंसल ने बताया कि जनता को जागरूक करने के लिए कलेक्ट्रेट में अलग-अलग स्थानों पर जागरूकता स्लोगन वाले फ्लैक्स भी लगाए गए हैं। इससे जनता भूमि खरीदने बेचने से पहले जानकारी प्राप्त कर सकती है।

होम स्टे की राष्ट्रीय नीति में समाहित होंगे उत्तराखंड के प्रावधान, सुविधाएं विकसित कर रही सरकार

देहरादून, एजेंसी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर केंद्र सरकार जोर दे रही है। इसी क्रम में सैलानियों के ठहरने व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना सबसे अहम कड़ी है और होम स्टे इसका बेहतर विकल्प है। इसके दृष्टिगत केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर होम स्टे नीति बनाने की तैयारी में है।

नीति आयोग की टीम ने कुछ समय पहले उत्तराखंड समेत चार राज्यों की होम स्टे नीति का अध्ययन किया था। अब आयोग अपनी संस्तुतियां केंद्र को भेजने जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड की होम स्टे नीति के प्रावधान भी शामिल किए जा रहे हैं। इनमें स्थानीय निवासियों के लिए सब्सिडी, पानी व बिजली की घरेलू दरें जैसे प्रावधान समाहित हैं।

नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन व तीर्थारंठन आर्थिकी से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। साल-दर-साल पर्यटकों व तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार इसी हिसाब से सुविधाएं भी विकसित कर रही है।

पहले से स्थापित पर्यटक स्थलों से इतर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण स्तर पर पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधा के दृष्टिगत वहां होम स्टे की पहल की गई है। अभी तक पांच हजार से अधिक होम स्टे स्थापित हो चुके हैं। होम स्टे के लिए सरकार अनुदान राशि देने के साथ ही पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट पर पंजीकरण इनके प्रमोशन में भी मदद करती है। साथ ही योजना में कई तरह की छूट के प्रावधान हैं।



योजना के लाभार्थी के लिए शर्त यही है कि होम स्टे का संचालक उसी में निवास करेगा और वहां ठहरने वालों को राज्य की सांस्कृतिक थाती से भी परिचित कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई अवसरों पर राज्य की होम स्टे की पहल की सराहना कर चुके हैं। इसके बाद सरकार ने योजना में कुछ और रियायत भी दी हैं।

न केवल उत्तराखंड, बल्कि केरल, गोवा व उत्तर प्रदेश में भी होम स्टे योजना के सार्थक परिणाम आए हैं। केंद्र सरकार को भी यह पहल बेहतर लगी है। इसी क्रम में केंद्र सरकार के निर्देश पर नीति आयोग की टीम ने बीते दिसंबर-जनवरी माह में उत्तराखंड समेत इन चार राज्यों की नीति का अध्ययन करने के साथ ही धरातलीय स्थिति का जायजा लिया।

लंबे समय से प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों की बढ़ेगी मुश्किलें, अब मुख्य सचिव की समिति लेगी निर्णय

देहरादून, एजेंसी।

लंबे समय से प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। प्रदेश सरकार प्रतिनियुक्ति, सेवा स्थानांतरण और बाह्य सेवा में कार्मिकों की तैनाती को हतोत्साहित करेगी। प्रतिनियुक्ति पर अधिकतम पांच वर्ष ही तैनाती मिलेगी। इसके बाद समय अवधि बढ़ाने की आवश्यकता होने पर पांच वर्ष की अवधि कूलिंग पीरियड होगी। इसके पूरी होने के बाद संबंधित कर्मचारी दोबारा आवेदन करेगा, लेकिन इस संबंध में निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।

किसी भी कार्मिक को सेवकाल में अधिकतम दो बार ही यह सुविधा मिलेगी। प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद मूल विभाग में लौटने से कन्नी काटी तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, अभियांत्रिकी सेवाओं समेत विभिन्न विभागों के कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। यह स्थिति तब है, जब मूल विभाग स्वयं कार्मिकों की कमी से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनियुक्ति के साथ ही बाह्य सेवा और सेवा स्थानांतरण के माध्यम से मूल विभाग से अन्यत्र कार्मिकों की तैनाती पर नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की व्यवस्था को हतोत्साहित करने के निर्देश दिए थे।

इस क्रम में वित्त सचिव वी षण्मनुम ने समस्त प्रमुख सचिवों, सचिवों एवं प्रभारी सचिवों के साथ मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयध्यक्षों को मंगलवार को आदेश जारी किया है। आदेश में प्रतिनियुक्ति, बाह्य सेवा और सेवा स्थानांतरण की परिभाषाओं को स्पष्ट करने के साथ ही इन माध्यम से तैनाती को लेकर नियम कड़े किए गए

सहायक निबंधकों को पर्वतीय जिलों में मिली पहली तैनाती, लोक सेवा आयोग से चयनित

देहरादून, एजेंसी। राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित छह सहायक निबंधकों को प्रदेश के विभिन्न पर्वतीय जिलों में पहली तैनाती दे दी गई है।

सहकारिता विभाग को राज्य लोक सेवा आयोग से मिले सहायक निबंधकों को पहली तैनाती पर्वतीय जिलों में दी गई है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, इन अधिकारियों के मिलने से विभागीय कार्यों में जहां तेजी आएगी, वहीं प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार होगा। सहकारिता मंत्री ने कहा, सरकार प्रशासनिक ढांचे को मजबूत कर योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटी है ताकि सहकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के अधिक कारगर, किसानों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को मिल सके।

इसी कड़ी में राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित छह सहायक निबंधकों को प्रदेश के विभिन्न पर्वतीय जिलों में पहली तैनाती दे दी गई है। जिसमें सौरभ कुमार को पौड़ी गढ़वाल, रोहित कुमार को अल्मोड़ा, प्रियाका घनसेला को उत्तरकाशी, आशीष को बागेश्वर, प्रवीण रावत को चंपावत और अंकित कुमार को पिथौरागढ़ जिले में नियुक्ति दी गई है।

डॉ. रावत ने बताया कि नव नियुक्त सहायक निबंधकों को डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में 12 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद इन्हें विभागीय जानकारी व अनुभव प्रदान करने के लिए सहकारी प्रबंध संस्थान देहरादून में 43 दिन का प्रशिक्षण दिया गया।



लंबे समय से प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों की बढ़ेगी मुश्किलें, अब मुख्य सचिव की समिति लेगी निर्णय



हैं। अब इनके माध्यम से सामान्य तैनाती तीन वर्ष होगी। इसे दो वर्षों के लिए वित्त विभाग की सहमति से बढ़ाया जा सकता है। यह अवधि अधिकतम पांच वर्ष होगी और इसे अब किसी भी दशा में आगे विस्तारित नहीं किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पूरी करने के बाद पांच वर्ष की अवधि कूलिंग पीरियड होगी। इसके पूरा होने के बाद ही प्रतिनियुक्ति, बाह्य सेवा और सेवा स्थानांतरण के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की समिति निर्णय लेगी। समिति में कार्मिक, वित्त, कर्मचारी के पैतृक विभाग और प्रतिनियुक्ति से संबंधित विभाग के उपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव बतौर सदस्य सम्मिलित हैं। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में तैनात कार्मिकों के लिए अधिकतम पांच वर्ष की सामान्य सीमा लागू नहीं होगी, लेकिन समय अवधि विस्तारित करने के लिए मुख्य सचिव की समिति से अनुमोदन लिया जाएगा। जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति में पांच वर्ष का समय शेष रह गया है, उन्हें प्रतिनियुक्ति, बाह्य सेवा एवं सेवा स्थानांतरण का लाभ नहीं मिलेगा।

कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन, बंद रखीं दुकानें

देहरादून, एजेंसी। देहरादून में किताबों की दुकानों पर कार्रवाई के विरोध में बुधवार को व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। व्यापारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम जापन सौंपा। व्यापारियों ने विरोध में बृहस्पतिवार को भी किताबों की दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया। व्यापारियों ने मांग पूरी न होने तक दुकान बंद रखने का एलान किया। मंगलवार को दून में पुलिस और प्रशासन की टीम ने किताबों की चार दुकानों को सील किया था। व्यापारियों का आरोप है कि टीम ने बिना सूचना दिए और अनाधिकृत रूप से दुकानों को सील किया। साथ ही मुकदमे दर्ज किए। विरोध में दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल और दून घाटी बुक सेलर एसोसिएशन के नेतृत्व में व्यापारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया।

साथ ही दुकानों को अनिश्चितकाल तक बंद करने और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसोन और एसोसिएशन के अध्यक्ष रणधीर ओरोड़ा ने कहा कि

प्रशासन ने बेबुनियाद मुकदमे दर्ज किए हैं। कहा कि मुकदमा वापस लिया जाए और सील की गई दुकानों को खोला जाए। ऐसा नहीं हुआ तो जल्द ही किताबों के साथ ही दून की सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा।

इस मौके पर संयोजक अशोक अग्रवाल, हरीश वीरमणि, पंकज डीवान, सुमित कोहली, रोहित बेहल, दीपू नागपाल, दिव्य सेठी, रजत गुप्ता, देवेंद्र साहनी, मन्नी अरोड़ा आदि मौजूद रहे।

व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को दिए जापन में 29 मार्च को हुई अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने ओवररैटिंग का हवाला देते हुए जो कार्रवाई की, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। इसके बावजूद आईएसबीएन का हवाला देते हुए कुछ किताबों को गलत और डुप्लीकेट बताया गया। कहा, आईएसबीएन किसी भी पुस्तक को कानूनी रूप से वैध या अवैध घोषित नहीं करता। यह केवल राश राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी की ओर से अलर्ट किया जाता है और इसका उल्लंघन किसी भी कॉपीराइट कानून या पायरेसी अधिनियम के तहत नहीं आता।



www.group5news.com/epaper

सम्पादकीय

कोर्ट की अवहेलना चिंताजनक

यह पहली बार नहीं है कि देश की शीर्ष अदालत को कहना पड़ा कि कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई न्याय के नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन है। लेकिन ऐसी बलपूर्वक की गई कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बुलडोजर की नाइंसाफी नजर आई। कोर्ट का कहना था कि वह बुलडोजरी अन्याय केवल झुगियायों व मकानों को ही नहीं गिरा रख है, बल्कि यह कानून की उचित प्रक्रिया व अनुच्छेद 21 का भी अतिक्रमण है। जो हर नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। शीर्ष अदालत ने क्यागवर्जन में घंटों को गिराए जाने को अमानवीय और अवैध बताते हुए



सैयद अहमर हसनैन

शहरी विकास प्राधिकरण को प्रत्येक पीड़ित घर के मालिक को दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान घटी उस घटना को तंत्र की संवेदनशीलता बताया जिसने बुलडोजर द्वारा झोपड़ी गिराए जाने पर एक बालिका अपनी किताबें पकड़कर भाग रही थी।

अदालत का कहना था कि तसवीर देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। साथ ही अधिकारियों की मनमानी और असंवेदशीलता को उजागर करती है। कहा गया कि अतिक्रमणकारियों को खुद की स्थिति को स्पष्ट करने का उचित अवसर दिए बिना बुलडोजर से उनके मकान या झोपड़ियों को ध्वस्त करना अन्याय जैसा ही है। जिससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रशासन का इरादा अनधिकृत निर्माण को हतोत्साहित करने के बजाय उन्हें सबक सिखाना लगता है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में शासन-प्रशासन कथित 'तत्काल न्याय' के बुलडोजर मॉडल को लागू करने में सबसे आगे रहा है। इस विवादस्पद कार्रवाई का बचाव करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कभी-कभी कुछ लोगों को उनकी समझ में आने वाली 'भाषा' में चीजों को समझाने की जरूरत होती है। जिसके मायने यह भी है कि ऐसे तत्वों को अदालतों द्वारा उन्हें दोषी या निर्दोष ठहराये जाने का इंतजार किए बिना ही दंडित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बीते साल नवंबर में, सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर के लगातार इस्तेमाल पर रोक

लगाने के लिये कई दिशा-निर्देश दिए थे। इसमें मकान आदि के ध्वस्तीकरण से पंद्रह दिन पहले कब्जाधारियों को सचेत करना भी शामिल था। अदालत ने तो यहां तक चेतावनी दी थी कि निर्देशों का अतिक्रमण करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जमीनी हकीकत में बदलाव नहीं आया। इसमें दो राय नहीं कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के प्रति सुवि-सहिष्णुता का नजरिया जरूरी है। अवैध निर्माण हटया जाना चाहिए, लेकिन सभी कायदे-कानूनों का पालन भी उतना ही जरूरी है। अदालत मानती रही है कि जल्दबाजी में बुलडोजर का इस्तेमाल

असंवैधानिक है और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। प्रयागराज व महाराष्ट्र में कई जगह लोगों ने आरोप लगाया कि नोटिस देने के चौबीस घंटों में ही उनके मकान गिरा दिए गए। ऐसी ही कार्रवाई नागपुर हिंसा के बाद आरोपियों के घर गिराने में की गई। कहा गया कि लोगों को अपील करने का भी मौका नहीं दिया गया। वैसे यह नैसर्गिक न्याय की अवहेलना है कि एक कथित दोषी के कृत्यों की सजा उसके पूरे परिवार को दी जाती है। उस घर में उस व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं। यह विडंबना है कि नागपुर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने आरोपियों की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगायी थी, लेकिन जब तक आदेशि पहुंचा तब तक स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर चुका था। वैसे हकीकत यह भी है कि कोई अवैध निर्माण रातोंरात खड़ा नहीं हो जाता। जब उसका निर्माण होता है तो स्थानीय प्रशासन की नजर उस पर क्यों नहीं जाती। एकाएक ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो जाती है कि उसे गिराने की तत्काल जरूरत पड़ती है। फिर तुरंत-फुरत बुलडोजर चल जाता है। सवाल यह भी कि हर छोटे-बड़े, धनाढ्य वर्ग, प्रभावशाली नेताओं के अवैध निर्माण पर पीला पंजा क्यों नहीं चलता? निस्संदेह, बुलडोजर की गति राजाश्रय के संरक्षण में ही तेज होती है।

केंद्रीय वक्फ अधिनियम लागू

वक्फ से जुड़ा भ्रम टूटा नहीं !

उर्दू शब्दकोश के अनुसार वक्फ का अर्थ है अल्लाह को समर्पित संपत्ति। हालांकि भारत में वक्फ के तहत भूमि अधिकतर शिंपे तरीके से निजी हित में कब्जियाकर इस्तेमाल होती रही। यह गंभीर पहलू कल के (02 अप्रैल 2025) संसदीय बहस में सुनाई नहीं दिया। बात 1955 की है जब देवदास सरकार ने पहला वक्फ बोर्ड गठित किया था, तभी एक साल बीते थे नेहरू सरकार को केंद्रीय वक्फ अधिनियम लागू किया। गंगार महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने औरंगाबाद मेंडलायुक्त का प्रशासक नियुक्त कर इस पहले वक्फ बोर्ड को गंग कर दिया था। वक्फ की अंधाधुनक इस्तेमाल के प्राक्षिक दौरे में शुरू हुई। इसे धार्मिक और सामाजिक प्रयोजनों के लिए संपत्तियों को समर्पित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। संघर्षों के साथ, वक्फ संस्थाएं बनीं, गिनका उद्देश्य समुदाय की भलाई को बढ़ावा देना था। एक कहानी और प्रचलित है कि एक बार खलीफा उमर ने खैबर में एक जमीन खरीदी। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से पूछा कि इस जमीन का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है। पैगंबर ने उन्हें सलाह दी कि इस जमीन को रोक लेना चाहिए। इसे बेचने, उधार में देने या विरासत में देने के बजाय, इसके फायदे को लोगों की जरूरतों पर खर्च करना चाहिए। इस तरीके से उस जमीन को वक्फ कर दिया गया, जिसका मतलब है कि उस जमीन से होने वाले लाभ सभी लोगों के लिए उपयोगी होंगे। कुछ इतिहास का संदर्भ देवें। वक्फ की संपत्ति की शुरुआत दो यात्रों के दान से हुई थी, जो हमलावर मोहम्मद गोरी से जुड़ी हुई हैं। बारहवीं शताब्दी के अंत में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो उसने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए मुसलमानों की शिक्षा और इबादत के लिए कदम उठाए। उसने मुस्लान की जामा मस्जिद के लिए दो गांव दान किए और इसे भारत में वक्फ का एक शुरुआती उदाहरण माना जाता है। मगर कलाओं में हिंदुओं की संपत्ति भी जबरन वक्फ के कब्जे में जाती रही। गनीमत है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद द्वारा कब्जियाई संपत्ति वक्फ नहीं बन पाई। इसी परिवेश में जानना जरूरी है कि भारत का नया संसद भवन यदि कांग्रेस शासन लौटा तो वक्फ संपत्ति घोषित कि जा सकती है। हालांकि यह संभावना 2021 में सच साबित हो रही थी। न्यायिक

अनमोल विचार

- संसार में सबकुछ खत्म धीरे-धीरे ही होता है पर उसको जानने में लोगों को सैंकड़ो साल लग जाते है ।
- जब तक हो सके मौन रहना सीखिए क्योंकि जहाँ बोलना है वहाँ आप अच्छे से खुद को व्यक्त कर सके ।
- लक्ष्य का आपका कब पूरा होगा किसी को नहीं पता बस जरूरत है उसे पूरा करने की बीच में कभी ना हटे ।
- व्यक्ति को अपनी दिनचर्या पर खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है ।
- सफल व्यक्तियों से अगर आप उनसे सफलता का राज पूछेंगे तो यही बतायेंगे के हर कार्य उन्होंने समय के साथ पूरा किया ।

स्वामी विवेकानंद लाहौर में अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक धार्मिक बैठक में भाग लेने गए थे । वहां स्वामी विवेकानंद एक छेते से बाजार से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक बुद्ध महिला एक दुकान से बर्तन खरीद रही थी। वह महिला गरीब थी और बाजार में बहुत परेशान दिख रही थी। स्वामी विवेकानंद ने महिला को देखा और बिना किसी भूमिका के उसके पास गए। उन्होंने महिला से पूछा, ‘आप इतनी परेशानी में क्या खरीदने की कोशिश कर रही हैं?’ महिला ने जवाब दिया, ‘वर्तन, जिन्हें घर में इस्तेमाल करना है।यह मेरे परिवार की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं’। स्वामी विवेकानंद ने महिला को देखा और बिना एक शब्द बोले अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर महिला को दे दिए। महिला चुपचाप पैसे लेकर चली गई। इसके बाद उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि हमारी सभ्यता और हमारी सोच का मूल यही होना चाहिए, ताकि हम किसी भी व्यक्ति को आत्मसम्मान और सम्मान से जीने का अवसर दे सकें।

Visit us at: www.group5news.com/epaper

शब्द कलश

बार्डर पर घुसपैठ चिंताजनक

घुसपैठियों के लिए आसान लांचिंग पैड नेपाल बॉर्डर के मदरसे



संजय सवसेना

पंड्रेसी राज्य नेपाल, भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। वैसे तो नेपाल के भारत से हमेशा प्रगाढ़ संबंध रहे हैं,लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन की भी दखलंदगी वस बढ़ी है। चीन के कई प्रोजेक्ट नेपाल में चल रहे हैं। गौणालिक रूप से देखे जाये तो चीन और नेपाल की सीमा 1439 किलोमीटर लम्बी है। वहीं भारत और नेपाल की सीमा की लम्बाई 1751 किलोमीटर है। यह सीमाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से जुड़ी हुई हैं। सबसे लम्बी सीमा 726 किलोमीटर बिहार से उसके बाद उत्तर प्रदेश से 551 और उत्तराखंड से 275 किलोमीटर और पश्चिमी बंगाल से 100 एंव सिक्किम से 99 किलोमीटर तक जुड़ी है। कभी यह सीमाएं लगभग पूरी तरह से खुली रहती थीं, लोग आसानी से बिना वीजा और पासपोर्ट के एक-दूसरे देशों में आ जा सकते थे। दोनों देशों के बीच व्यापार करने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं था,लेकिन अब हालात काफी बदल गये हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब इन सीमाओं को लांचकर अराजक तत्व और आतंकवादी ताकतें भी भारत में प्रवेश करने लगी हैं। सीमा खुली होने का फायदा उठाकर पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों सहित कई देशों के घुसपैठिों और आतंकवादी भारत में आते है और यहां आतंक फैलाते हैं। यहीं वजह है नेपाल और भारत के बीच की सीमा क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ सालों में खासी चिंता देखी गई है।

सबसे खास बात यह है कि इन घुसपैठियों और आतंकवादियों के लिये भारत-नेपाल के बार्डर के बार्डर पर बने मदरसे सुविधित रिकाना बन कर उभर रहे हैं। कई मदरसों के तार भारत विदेशी ताकतों के साथ जुडे हुए हैं। नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में सतिध गतिविधियों का बढ़ना और आतंकवादियों का घुसपैठ करने का प्रयास स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा रहा है। खासकर, 28 फरवरी को काठमांडू में हुई हिंस ने इस क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है।यह हिंस सिर्फ नेपाल तक ही सीमित

नजीर बनेगी सुप्रीम कोर्ट की संवदेनशीलता

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले



रोहित माहेश्वरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 17 मार्च के एक फैसले में कल था कि पीड़िता के दस्तन को रूखा और पायजामे की डेरी तोड़ने को बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामले में नली गिना जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से पूरा देश हतप्रभ था। कोर्ट के फैसले पर देशभर में धर्वा का दौर तो शुरू हुआ ही, वहीं यह फैसला सवालों के पेरे में भी था। वी द तुमेन ऑफ इंडिया नामक संगठन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कल कि क्योंकि फैसला पूरी तरह से अस्पेदनशील और अमानवीय नजरिए को दिखाता है, इसलिए फैसले पर रोक लगाकर का स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर न्याय की संवेदनशीलता को मजबूती प्रदान की है। जिस केस में यह फैसला सुनाया गया, यह मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जनापद के पटियाली थाना क्षेत्र में एक किशोरी से जुड था।

‘यह मामला नाबालिंग से दुर्कर्म का है। जो बेहद पवन, आकाश और अशोक मोटरसाइकिल पर उहें रास्ते में मिले। मां का कहना था कि पवन ने उनकी बेटी को घर छोड़े का भरोसा दिलाया और इसी विश्वास के तहत उन्होंने अपनी बेटी को जाने दिया। लेकिन रास्ते में मोटरसाइकिल रोककर इन तीनों लोगों ने लड़की से बदतमीजी की और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ। उसे पुल के नीचे धसीया

और उसके पायजामे का नाडू तोड़ दिया। लेकिन तभी वहां से ट्रैक्टर से गुजर रहे दो व्यक्तिों सतीश और भूरे ने लड़की का रोना सुना। अभियुक्तों ने उन्हें तमंचा दिखाया और फिर वहां से भाग गए। जब नाबालिंग की मां ने पवन के पिता अशोक से शिकायत की तो उहें जान से मारने की धमकी दी गई जिसके बाद वे थाने गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला कासगंज की विशेष कोर्ट में पहुंचा जहां पवन और आकाश पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), पॉक्सो एक्ट की धारा 18 (अपराध करने का प्रयास) और अशोक के खिलाफ धारा 504 और 506 लगाई गई। इस मामले में सतीश और भूरे गवाह बने, लेकिन इस मामले को अभियुक्तों की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने फैसला सुनते हुए कहा था-पीड़िता के निजी अंगों को पकड़ना और पायजामे का नाडू तोड़ना दुर्कर्म या दुर्कर्म की कोशिश नहीं मानी जा सकती। इस फैसले पर न्यायविदों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत तलख प्रतिक्रियाएं जताई थीं। ‘वी द तुमेन ऑफ इंडिया’ की अर्जी पर सर्वोच्च अदालत को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की न्यायिक पीठ ने कहा कि ‘यह मामला नाबालिंग से दुर्कर्म का है। जो बेहद गंभीर है। खेद है कि फैसला देने वाले जज के खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। यह फैसला जज का अस्पेदनशील और अमानवीय नजरिया दिखाता है, लिहाजा इस पर रोक जरूरी है।’ बेंच ने माना कि फैसला लिखने में संवेदनशीलता की कमी दुष्टिगोचर होती है। कोर्ट का मानना था कि जब फैसला चार माह



तक सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया तो यह नहीं कहा जा सकता कि इस पर गंभीर मंथन नहीं हुआ। वहीं शीर्ष अदालत ने इस मसले पर केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। केंद्र के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने भी पीठ के फैसले से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि दुर्कर्म की तैयारी थी, दुर्कर्म नहीं किया गया, जज के फैसले में ऐसा कहा गया है। यह बेहद गंभीर टिप्पणी है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ का कहना था कि दुराचार करने की कोशिश और अपराध का तैयारी के बीच के अंतर को सही ढंग से समझना चाहिए। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को आईपीसी व पॉक्सो एक्ट की हल्की धाराओं में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। जहां अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 18 लगाई गई। जिसको अभियुक्तों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी गई। माना गया कि इसका समाज में गलत संदेश जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसके चलते ही एक महिला संगठन वी द वूमन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

कालांतर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत-संज्ञान लिया। उल्लेखनीय है कि एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले को पलट कर कानून की संवेदनशीलता को सबल दिया था। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 में कहा था कि किसी बच्चे के यौन अंगों को यौन इरादे से रूखा पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत यौन हिंसा माना जाएगा। अब चाहे इसमें त्वचा का संपर्क नहीं हुआ हो। कोर्ट का मानना था कि अभियुक्त का इरादा ज्यादा मायने रखता है। बहरहाल अदालत है कि ‘दुर्कर्म’ का भाव क्या होता है? आरोपितों ने उस नाबालिंग लड़की के निजी अंगों को क्यों पकड़ था? पायजामे का नाडू क्यों तोड़ या खोला था? और उस लड़की को पुलिस के नीचे क्यों ले जाना चाहते थे? इन सभी हरकतों में दुर्कर्म की नीयत अथवा मंशा साफ थी, लिहाजा एक आम आदमी के तौर पर हम इसे दुर्कर्म ही मानेंगे। आमतौर पर फैसले के ऐसे चरण में सर्वोच्च अदालत हस्तक्षेप नहीं करती और न ही रोक लगाती, लेकिन न्याय के नाम पर यह अर्नेतिक था और न्यायिक सिद्धांतों से परे था, लिहाजा विवादित हिस्से पर रोक लगानी पड़ी। वो तो लड़की जोर से चीखती रही, लिहाजा कुछ लोग उसे बचाने को वहां आ गए और आरोपित वहां से भाग गए, नतीजतन लड़की दुर्कर्म के दंश से बच गई। अलबत्ता दुर्कर्म हो सकता था। वर्ष 2021 में सर्वोच्च अदालत ने आरोपित पैतृक और स्त्री-द्वेषी रवैये के खिलाफ एक व्यापक चेकलिस्ट जारी की थी। खासकर न्यायिक फैसलों के संदर्भ में यह किया गया था, लेकिन अश्विष्ठ ध्यान नहीं दिया गया। निचली अदालतों में स्थितिवां काफी खराब है।

आज का पंचांग

4 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। सप्तमी तिथि शुक्रवार रात 8 बजकर 13 मिनट तक रहेगी। 4 अप्रैल को नवरात्रि का सातवां दिन है। शुक्रवार रात 9 बजकर 45 मिनट तक शोमन योग रहेगा। साथ ही 4 अप्रैल को पूरा दिन, पूरी रात पाद कर शनिवार सुबह 5 बजकर 21 मिनट तक आर्द्र नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा शुक्रवार को अन्नपूर्णा परिक्रमा शुरू हो रही है। 04 अप्रैल 2025 का शुभ मुहूर्त चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि- 04 अप्रैल 2025 को रात 8 बजकर 13 मिनट तक शोमन योग- 04 अप्रैल 2025 को रात 9 बजकर 45 मिनट तक आर्द्र नक्षत्र- 04 अप्रैल 2025 को पूरा दिन, पूरी रात पाद कर शनिवार सुबह 5 बजकर 21 मिनट तक 04 अप्रैल 2025 पद-रविवार- नवरात्रि का सातवां दिन, अन्नपूर्णा परिक्रमा शुरू सूर्योदय-सूर्यास्त का समय सूर्योदय- सुबह 6:07बजे सूर्यास्त- शाम 6:40 बजे

नेपाली सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि बांग्लादेश के एक आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन के आतंकवादी को नेपाल क्षेत्र में पनाह दी गई थी। इसी तरह, अलकायदा इन इंडियन सब काटिनेट (एक्यूआईएस) जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन भी नेपाल के बदलते हालात का फायदा उठा सकते हैं। इन संगठनों का लक्ष्य भारत में घुसपैठ कर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना हो सकता है। इस संदर्भ में पूर्व आईबी अधिकारी प्रवीण गर्ग का कहना है कि काठमांडू में जो हिंसा हुई, वह नेपाल में राजाबादी आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश हो सकती है। उनके अनुसार, बांग्लादेश को अस्थिर करने के बाद, पाकिस्तान और चीन के सुरक्षा एजेंसियां नेपाल को भी अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। इन दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों की नेपाल में सक्रियता इस संभावना को और मजबूत करती है। खासकर इस साल की शुरुआत से इन दोनों देश की एजेंसियों की भारत से सटे नेपाली क्षेत्र में बढ़ी सक्रियता एक गंभीर चिंता का विषय है। चौकाने वाली बात यह भी है कि जो नेपाल कुछ वर्षों तक हिन्दू राष्ट्र होता था, वह अब शरिया कानून की गंगा में उठने लगी है, जो कि पहले नेपाल के मुसलमानों के लिए एक दूर का ख्वाब था...



है। वैसे मुस्लिमों की बढ़ती आबादी और शरिया कानून की वकालत के बीच हिन्दू संगठन भी एक बार फिर से नेपाल को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की वकालत करने लगे हैं। हालांकि, राजनीति के कई जानकार नेपाल में शरिया कानून की मांग को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटीलजेंस द्वारा प्रायोजित किया हुआ कदम बता रहे हैं, जो नेपाल को राजनीतिक रूप से अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा है। नेपाली सीमा पर बढ़ रही इन आतंकी गतिविधियों की ओर इशारा करते हुए आंकड़े भी सामने आए हैं, जो यह साबित करते हैं कि भारत में आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयास बढ़े हैं। तब बाईर पर चल रहे मदरसों की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्तता की कि जाये तो इसके कई केस मिल जाते हैं। इसी वर्ष के शुरुआती महीनों में मटर-धमऊर क्षेत्र के पिलर संख्या 501-6 के पास से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था, जिसे मदरसा मदीनतुल में शरण मिली थी। इसी तरह, 2024 में हिजबुल मुजाहिदीन के तीन आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, जो नेपाली सीमा के पास स्थित एक मदरसे में ठहरे हुए थे। 2020 में पापलुर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक ट्रेनिंग कमांडर राशिद को गिरफ्तार किया गया था, जो नेपाल सीमा से सटे मदरसे में सक्रिय था। इस तरह की घटनाएं यह साबित करती हैं कि नेपाल सीमा पर आतंकवादियों की सक्रियता बढ़ रही है, और सुरक्षा एजेंसियों को इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है।इसके लिये मदरसों की पेंच करसना जरूरी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कल था-पीड़िता के निजी अंगों को पकड़ना और पायजामे का नाडू तोड़ना दुर्कर्म या दुर्कर्म की कोशिश नहीं मानी जा सकती। इस फैसले पर न्यायविदों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत तलख प्रतिक्रियाएं जताई थीं। ‘वी द तुमेन ऑफ इंडिया’ की अर्जी पर सर्वोच्च अदालत को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की न्यायिक पीठ ने कहा कि ‘यह मामला नाबालिंग से दुर्कर्म का है। जो बेहद गंभीर है। खेद है कि फैसला देने वाले जज के खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। यह फैसला जज का अस्पेदनशील और अमानवीय नजरिए को दिखाता है, इसलिए फैसले पर रोक लगाकर न्याय की संवेदनशीलता को मजबूती प्रदान की है। जिस केस में यह फैसला सुनाया गया, यह मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जनापद के पटियाली थाना क्षेत्र में एक किशोरी से जुड था।

आज का राशिफल

मेष :अजनी अपनी घरेलू कीमती वस्तुएं समालोचर रखें। खासकर महिलाएं विशेष सावधानी रखें। किचन में आगजल घोट लग सकती है। अपेक्षित करों में विलंब हो सकता है। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। वहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें।	वृषभ :आपको आज का दिन कारोबार हेतु लाभदायक बताने होगा। नौकरी वर्ग में चैन रहेगा। वन प्राप्ति सुगम होगी। घरेलू कार्य समय पर होंगे। सुख-शान्ति बनी रहेगी। यथन व कमजोरी रहेगी। अतिवाहियों के लिए वैश्विक प्रस्ताव आ सकता है।
सिंह :नौकरीपेशा वर्ग को मासिक आय में निरिपता बनी रहेगी। व्यवसाय-व्यापार लाभदायक रहेगा। पुराने शत्रु सक्रिय रहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रहेगा। किसी व्यक्ति से बेवकूफ विवाद हो सकता है। दुःखद समाचार प्राप्त हो सकता है।	कन्या :नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। धन के निवेश में रूढ़ विवेक का प्रयोग करें। व्यापार में धनगर्जन होगा। घर-परिवार के छोटे सदस्यों के अध्ययन कार्य प्रारंभ होगा। जलकन महसूस रहेगी। शारीरिक रहेगी। दुरुजन खलि पहुंचा सकते हैं।

धनु :अपनी कीमती वस्तुएं समालोचर रखें। नौकरी में अधिकारी की अपेक्षाएं बढ़ेंगी। तनाव रहेगा। दूसरों के कार्य की जवाबदारी न लें। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रेम-प्रसंग में जोखिम न लें। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे।	मकर : आपकी व्यावसायिक यात्रा आज सफल रहेगी। बकाया वसूली के प्रयास मानोत्कूल रहेगे। आप भी अपनी देनदारी समय पर चुका पाएंगे। नौकरी वर्ग को लाभ के अवसर हय आएं। भाग्य का साथ मिलेगा। धनगर्जन होगा।
---	---

मिथुन : परिवारजनों के साथ किसी बड़ी भूमि व भवन के खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी। व्यापार से बड़ा लाभ लेने के योग है। परीक्षा व साक्षात्कार में सफलता प्राप्त होगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यापार लाभदायक रहेगा।	तुला :आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। जलकन न करें। धनगम होगा। थकान महसूस रहेगी। शारीरिक आराम की आवश्यकता रहेगी।
--	--

कुंभ : नौकरी पेशा के कार्यप्रणाली में आज सुधार होगा। धन लाभ के अवसर हय आएं। मित्रों की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा। कारोबारी अनुबंध होंगे। आर्थिक-कुशका के चलते निर्णय लेने की धमता प्रभावित होगी।	
---	--

कर्क : दिव्यार्थ वर्ग सफलता सहित करेगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। धनलाभ के अवसर हय आएं। पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बनेगा। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। पारिवारिक वित्त बनी रहेगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा।	वृश्चिक : कार्य में उत्साह बढ़ेगा। कार्य की बाधा दूर होकर स्थिति लाभप्रद रहेगी। कोई बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अप्रत्याशित लाभ के योग है। सट्टे व लॉटरी से दूर रहें। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। शरीर स्वस्थ नहीं देगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
--	---

मीन :आज व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। कानूनी अड़न दूर होकर स्थिति अनुकूल होगी। नौकरीपेशा के आय में अच्छी वृद्धि होगी। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। पूजा-घाट में मन लगेगा। किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है।	
--	--

ट्रंप ने विभिन्न देशों पर व्यापक नए शुल्क की घोषणा की, महंगाई और व्यापार युद्ध का खतरा बढ़ा

» वाशिंगटन, माषा।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशों पर दूरगामी प्रभाव वाले नए शुल्क लगाने की घोषणा की। इसमें चीन से आयात पर 34 प्रतिशत कर और यूरोपीय संघ (ईयू) और अन्य पर 20 प्रतिशत कर लगाया गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना के काफी हद तक व्धस्त होने और व्यापक व्यापार युद्ध शुरू होने का खतरा है।ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में यह घोषणा करते हुए कहा कि वे दर्जनों ऐसे देशों पर शुल्क दरे बढा रहे हैं जो अमेरिका के साथ सार्थक व्यापार अधिशेष रखते हैं। साथ ही, उन्होंने आर्थिक आपातकाल के जवाब में सभी देशों से आयात पर 10 प्रतिशत का बेसलाइन कर लगाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शुल्क घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा निर्मित वैश्विक व्यापार प्रणाली का वर्णन करने के लिए आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया।

उन्होंने कहा, हमारे देश को अन्य देशों द्वारा लूटा गया और जबर्दस्ती की गई। यह कदम ऐतिहासिक कर वृद्धि के बराबर है जो वैश्विक व्यवस्था को टूटने के कगार पर पहुंचा सकता है। यह कई अमेरिकियों के लिए एक ऐसे बदलाव की शुरुआत है, जो शायद दर्दनाक होगा। इससे मध्यम वर्ग की जरूरत वाली चीजें जैसे घर, वाहन और कपड़े महंगे होंगे। वहीं शांति और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए ऋणधनों में बाधा उत्पन्न होगी। ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिकी सरकार के लिए सैकड़ों अरबों का नया राजस्व लाते और वैश्विक व्यापार में निष्पक्षता बहाल करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है।...लेकिन अगर ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रंप ने शुल्क लगाने के लिए राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल की घोषणा की। उन्होंने वाद किया है कि करों के परिणामस्वरूप



भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के जवाबी शुल्क की आलोचना की

न्यूयॉर्क। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों और प्रवासी समुदाय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्क को बिना सोचा समझा और आत्म-विनाशकारी करार देते हुए इसकी आलोचना की है। अमेरिकी सांसदों और प्रवासी समुदाय के इन लोगों ने दोनों देशों के नेताओं से इन चुनौतियों से निपटने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर व्यापक रूप से 26 प्रतिशत का रियायती जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से विभिन्न देशों पर शुल्क लगाने की घोषणा करते हुए कहा, भारत हमसे 52 प्रतिशत शुल्क लेता है, इसलिए हम उनसे इसका आधा - 26 प्रतिशत शुल्क लेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए उच्च शुल्कों का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लगभग 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है। सांसदों ने यह भी कहा कि ट्रंप के जवाबी शुल्क से भारतीय सामान की बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि ट्रंप का जवाबी शुल्क कामकाजी परिवारों पर एक प्रकार का कर है, ताकि वह सबसे धनी अमेरिकियों के लिए करों में कटौती कर सकें। इलिनोइस से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद कृष्णमूर्ति ने कहा, नवीनतम तथाकथित मुक्ति दिवस शुल्क बिना सोचा समझा और आत्मघाती हैं, जो इलिनोइस को ऐसे समय में वित्तीय पीड़ा पहुंचा रहे हैं, जब लोग पहले से ही अपने छोटे व्यवसायों को बचाए रखने और भोजन की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति ने कहा कि जवाबी शुल्क वैश्विक मंच पर अमेरिका को अलग-थलग कर देते हैं, अमेरिका के सहयोगियों को अलग-थलग कर देते हैं और उसके विरोधियों को सशक्त बनाते हैं। कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी नागरिकों से आग्रह किया कि वे ट्रंप से कहें कि वे देश को मंदी की ओर ले जाने से पहले अपनी विनाशकारी शुल्क नीतियों को समाप्त करें। उन्होंने कहा कि जवाबी शुल्क की अमेरिकी अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कोई भूमिका नहीं है।

कारखानों की नौकरियां अमेरिका में वापस आ जाएंगी, लेकिन उनकी नीतियों से अचानक आर्थिक मंदी का खतरा है क्योंकि उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कीमतों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण चुनावी वादा पूरा किया क्योंकि उन्होंने 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति अधिनियम के तहत कांग्रेस के बिना व्यापार भागीदारों पर जवाबी शुल्क लगाए

हैं। लेकिन बुधवार को उनकी यह कार्रवाई मुद्रास्फीति से निपटने के लिए पिछले साल के चुनाव में ट्रंप के मतदाता जनादेश को खतरे में डाल सकती है। राष्ट्रपति की उच्च दरें उन विदेशी इकाइयों को प्रभावित करेंगी जो अमेरिका को खरीदने से ज्यादा सामान बेचती हैं। ट्रंप प्रशासन ने अनिवार्य रूप से उन देशों के साथ व्यापार असंतुलन के बराबर राजस्व जुटाने के लिए अपनी शुल्क दरों की गणना की है। ट्रंप ने फिर उस दर को आधा कर दिया और खुद को बहुत दयालु बताया। व्हाइट हाउस का कहना है कि शुल्क और अन्य व्यापार असंतुलन के कारण पिछले साल, 200 अरब डॉलर का असंतुलन हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुझाव दिया कि अन्य देशों को अपने आयात



पर नए शुल्क को कम करने के लिए कई तरह की कार्रवाई करनी पड़ सकती है, और उन देशों द्वारा जवाबी शुल्क लगाने से स्थिति और खराब हो सकती है।

करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा : ट्रंप

अमेरिका के जवाबी शुल्क पर दुनिया भर के नेताओं ने दी सधी प्रतिक्रिया

» बैकॉक, माषा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशों पर दूरगामी प्रभाव वाले नए शुल्क लगाने की घोषणा की। इसमें चीन से आयात पर 34 प्रतिशत कर और यूरोपीय संघ (ईयू) और अन्य पर 20 प्रतिशत कर तथा भारत पर व्यापक रूप से 26 प्रतिशत का रियायती जवाबी शुल्क लगाया गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना के काफी हद तक व्धस्त होने और व्यापक व्यापार युद्ध शुरू होने का खतरा है। ट्रंप इन आयात करों को जवाबी शुल्क कहते हैं और इनकी सीमा 10 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक है। सफल शब्दों में कहें तो अमेरिका अपने व्यापारिक साझेदारों पर उतना ही शुल्क लगाएगा जितना वे लगाएंगे। ट्रंप के अनुसार, ये देश दशकों से अमेरिका के साथ यहीं करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा, करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है...लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। राष्ट्रपति ने वाद किया कि करों के परिणामस्वरूप अमेरिका के कारखानों में नौकरियां वापस आऊंगी, लेकिन उनकी नीतियों से अचानक आर्थिक मंदी का खतरा है क्योंकि उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कीमतों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने इसे न केवल एक आर्थिक मुद्दा बताया, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न भी बताया, जो हमारी जीवन-शैली के लिए खतरा है। ट्रंप की इस घोषणा के बाद वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल मच गई। बृहस्पतिवार को अमेरिकी शेयर बाजार में तीस प्रतिशत तक की गिरावट आई और तोक्यों के बाजार में एशिया में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। तैने की कीमतों दो डॉलर प्रति बैरल से अधिक गिर गईं और बिटकॉइन की कीमत में 4.4 प्रतिशत की गिरावट आई। ट्रंप की घोषणा के बाद ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि अमेरिका ब्रिटेन का सबसे करीबी सहयोगी बना हुआ है। व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने कहा कि ब्रिटेन को उम्मीद है कि वह ट्रंप द्वारा घोषित ब्रिटिश वस्तुओं पर 10 प्रतिशत शुल्क के प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापार समझौता कर लेगा। उन्होंने कहा, कोई भी व्यापार युद्ध नहीं चाहता



और हमारा इरादा समझौता सुनिश्चित करना है। इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी ने ईयू के विरुद्ध नए 20 प्रतिशत शुल्क को गलत बताते हुए कहा कि इससे किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होगा। मेलोनी ने फेसबुक पर पोस्ट कर कहा, हम अमेरिका के साथ एक समझौते की दिशा में काम करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जिसका उद्देश्य एक व्यापार युद्ध से बचना है। ब्राजील की सरकार ने कहा कि वह इस मामले को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में ले जाने पर विचार कर रही है। बाद में ब्राजील की कांग्रेस ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया, जो ब्राजील की सरकार को देश के सामान पर शुल्क लगाने वाले किसी भी देश या व्यापार समूह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति देता है। अमेरिका को सबसे बड़े निर्यातकों में से एक एशियाई देशों ने प्रभावित होने वाले वाहन निर्माताओं एवं अन्य व्यवसायों का समर्थन करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का संकल्प जताया। दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक नेता प्रधानमंत्री हान डक-सू ने अधिकारियों से कहा है कि वे नए 25 प्रतिशत शुल्क के संभावित प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए व्यापारिक समूहों के साथ काम करें ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि चीन अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से जवाबी कदम उठाएगा।

अमेरिका ने अपने कर्मियों पर चीनी नागरिकों के साथ रोमांटिक, यौन रिश्ता रखने पर प्रतिबंध लगाया

» वाशिंगटन, माषा।

अमेरिकी सरकार ने चीन में अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों, साथ ही परिवार के सदस्यों और सुरक्षा मंजूरी प्राप्त ठेकेदारों पर चीनी नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का रोमांटिक या यौन रिश्ता रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक्सिस्टेंस ऐड (एपी) को इस बारे में जानकारी मिली है। मामले से उपवात चार लोगों ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर एपी को इस नीति के बारे में बताया जिसे जनवरी में अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्नॉल्ड ने चीन छोड़ने से कुछ समय पहले लागू किया था। कुछ अमेरिकी एजेंसियों ने पहले से ही ऐसे रिश्तों को लेकर सख्त नियामन लगा रखे हैं।

हालांकि, अन्य देशों में अमेरिकी राजनयिकों के लिए स्थानीय लोगों के साथ डेटिंग करना और उनसे शादी तक करना भी अप्रामाण्य नहीं है। पिछले साल गर्मियों में इस

नीति को सीमित रूप में लागू किया गया था, जिसके तहत अमेरिकी कर्मियों को चीन में अमेरिकी दूतावास और पांच वाणिज्य दूतावासों में गार्ड एवं अन्य सहायक कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले चीनी नागरिकों के साथ रोमांटिक और यौन रिश्ता रखने पर रोक लगा दी गई थी। प्रतिबंध से अवगत दो लोगों ने एपी को बताया कि नई नीति पर पहली बार पिछली गर्मियों में चर्चा हुई थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी संबंधी प्रतिनिधि सभा की चयन समिति ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। नई नीति के दायरे में मुख्य भूमि चीन में अमेरिकी मिशनों को शामिल किया गया है, जिसमें बीजिंग में दूतावास और गुआंगझू, शंघाई, शेनयांग और वुहान में वाणिज्य दूतावास के साथ हांगकांग के अर्द्ध-स्वायत्त क्षेत्र में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास शामिल हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 27 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाया

न्यूज ब्रीफ

वैश्विक व्यवस्था में हो रही उथल-पुथल, हर क्षेत्र को अपने बारे में स्वयं सोचना होगा : जयशंकर

» बैकाक, माषा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित जवाबी शुल्क के बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि दुनिया स्व-सहायता के युग की ओर बढ़ रही है और हर क्षेत्र को खुद पर ध्यान देना होगा। जयशंकर ने बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिन्सटेक) के 20वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छोटी आपूर्ति श्रृंखलाएं और निर्यात पड़ोसी अब पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने कहा, वास्तविकता यह है कि दुनिया स्व-सहायता के युग की ओर बढ़ रही है। हर क्षेत्र को खुद पर ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वह खाद्य, ईंधन और उर्ध्वक आपूर्ति, टीके या त्वरित आपदा प्रतिक्रिया हो। विदेशमंत्री ने कहा, हम अपनी आंखों के सामने इसे घटित होते देख रहे हैं। समय वास्तव में बदल गया है। छोटी आपूर्ति श्रृंखलाएं और निर्यात पड़ोसी पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।



जयशंकर जहां बिन्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए यहां हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छठे बिन्सटेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बृहस्पतिवार को यहां पहुंचे। मंत्री ने कहा कि बिन्सटेक शिखर सम्मेलन बहुत अनिश्चित और अस्थिर समय में हो रहा है जबकि वैश्विक व्यवस्था उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा, इससे हमें बिन्सटेक को और अधिक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। नई व्यवस्था, जिसकी रूपरेखा अब दिखाई देने लगी है, मूल रूप से अधिक क्षेत्रीय और एजेंडा-विशिष्ट है। मंत्री ने कहा, वह युग जब कुछ शक्तियां अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अपने हाथ में लेती थीं,

भारत और थाईलैंड ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन किया : प्रधानमंत्री मोदी



» बैकाक, माषा।

भारत और थाईलैंड ने अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का बृहस्पतिवार को फैसला किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, समावेशी और नियमित आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं तथा विस्तरवाद के बजाय विकास की नीति में विवास करते हैं। मोदी ने यह टिप्पणी थाईलैंड की अपनी समकक्ष पंतोगतान् शिनावत्रा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस सम्मेलन में की। इस वार्ता के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की। मोदी ने शिनावत्रा के साथ हुई बातचीत के बारे में कहा, हमने भारत के पूर्वीत राज्यों और थाईलैंड के बीच पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया है।

हमने आपसी व्यापार, निवेश और व्यवसायों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एमएसएमई, हथकरघा और हस्तशिल्प में सहयोग के लिए भी समझौते किए गए हैं। मोदी ने कहा कि भारत की एकट्र इंस्ट नीति और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण में थाईलैंड का विशेष स्थान है। मोदी ने कहा आज हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच रणनीतिक वार्ता स्थापित करने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत आसियान में एकता और केंद्रीयता का पूर्ण समर्थन करता है। मोदी ने कहा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हम दोनों एक मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं। हम विस्तरवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपनी यात्रा के अवसर पर 18वीं

प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड की अपनी समकक्ष शिनावत्रा के साथ वार्ता की

बैकाक। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार

को थाईलैंड की अपनी समकक्ष पंतोगतान् शिनावत्रा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। मोदी बृहस्पतिवार को छठे बिन्सटेक (बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर थाईलैंड पहुंचे, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने रामकिपन - थाई रामायण की मनमोहक प्रस्तुति भी देखी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विशेष औपचारिक स्वागत। थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने आज बैकाक के गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा, दोनों नेता भविष्य में भारत-थाईलैंड साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए व्यापक चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने बैकाक पहुंचने के बाद रामकिपन की प्रस्तुति देखी। पीएमओ ने कहा कि यह भारत और थाईलैंड के बीच समृद्ध सभ्यतागत संबंधों को प्रदर्शित करता है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुड़ाव थाई रामायण, रामकिपन की मनोरम प्रस्तुति देखी। यह वास्तव में शानदार अनुभव था, जिसमें भारत और थाईलैंड के बीच साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया।



शताब्दी के रामायण भित्ति चित्रों पर आधारित एक विशेष डक टिकट जारी करने के लिए थाईलैंड सरकार का आभारी हूं। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शिनावत्रा ने उन्हें त्रिपिटक भेंट किया। उन्होंने कहा बुद्ध की भूमि भारत की ओर से, मैंने इसे हाथ जोड़कर स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि भारत और थाईलैंड के बीच

सदियों पुराने संबंध उनके गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक डोर से बंधे हैं। मोदी ने कहा कि बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे देश के लोगों को हर स्तर पर जोड़ा है। उन्होंने कहा, अनुप्रास नालंदा तक विद्वानों का आना-जाना हुआ है। रामायण कथा थाईलैंड के लोक जीवन में गहराई से समाई हुई है।

म्यांमा भूकंप

भूकंप के समय मुस्लिम रमजान के अंतिम जुमे (शुक्रवार) पर अलविदा की नमाज अदा कर रहे थे

मांडले में भारतीय टीम बचाव कार्य के साथ स्थानीय लोगों का दिल भी जीत रही

» मांडले (म्यांमा), माषा।

म्यांमा में गत शुक्रवार को 7.7 तीव्रता का भूकंप आने और उसके बाद मदद को पहुंची भारतीय टीम विपरीत परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य को अंगमा तो दे ही रही है साथ ही स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान कर उनका दिल भी जीत रही है। इसी का उदाहरण मांडले में मलबे से एक शव को निकालते समय देखने को मिला। मलबे में फंसे शव को देखकर प्रतीत होता था कि मलबे में एक उसका बच्चा उस समय भूकंप की घंटे में आ गए जब वे नमाज पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के कर्मियों ने पूर्व शाही राजधानी मांडले में स्ट्रीट 86ए के पास इस आपदा स्थल पर स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए शव निकालने से कदम पीछे खींच लिया।



लेकिन समय गुजरने के साथ ही शव सड़ने लगा था। परिजनों को एहसास हुआ कि शव को पूरी तरह से निकालने के लिए उनके पास विशेषज्ञता का अभाव है, इसलिए वे हिचकिचाते लगे। उनकी शुरुआती अनिच्छा बाद में अपील में बदल गई। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ कर्मियों ने अपना कार्य पुनः शुरू किया, महिला के शव को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला तथा नमाज़ की उसकी अंतिम मुद्रा की गरिमा को बनाए

रखा। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, जो लोग मदद स्वीकार करने में झिझक रहे थे, अब वे आभार जताते थक नहीं रहे हैं। म्यांमा में एनडीआरएफ खोज एवं बचाव अभियान दल के उप टीम लीडर डिटी कमांडर कुणाल तिवारी ने बताया कि टीम को शव प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है। आदम हुसैन (65) ने बताया कि भूकंप उस समय आया जब मुस्लिम पवित्र महीने रमजान के अंतिम जुमे (शुक्रवार) पर अलविदा की नमाज अदा कर रहे थे। राहत और बचाव कार्यों के लिए मांडले शहर को चार सेक्टरों- अल्फा, ब्रावो, चाली और डेल्टा में बांटा गया है। स्थानीय अधिकारियों ने डेल्टा को भारत को आवंटित किया है, जबकि अन्य तीन सेक्टरों को चीन, रूस और म्यांमा अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा संभाला जा रहा है। एनडीआरएफ टीम ने

म्यांमा भूकंप : मृतकों की संख्या बढ़कर 3,085 हुई

बैकाक। म्यांमा में करीब एक सप्ताह पहले आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बृहस्पतिवार को बढ़कर 3,085 हो गई। देश की सैन्य सरकार ने यह जानकारी दी। एक संक्षिप्त बयान में सेना ने कहा कि 4,715 लोग घायल हुए हैं तथा 341 लापता हैं। पिछले शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र म्यांमा के दूरपेरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था। इससे कई इलाकों में हजारों इमारतें ढह गईं, सड़कें टूट गईं और पुल नष्ट हो गए। स्थानीय मीडिया में हवाहवातों की जो संख्या बताई गई है वह आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है। चूंकि दूरसंचार सेवाएं व्यापक रूप से बंद हैं तथा कई स्थानों तक पहुंचना कठिन है इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जैसे-जैसे अधिक विवरण सामने आएंगे, मृतक संख्या में तेजी से वृद्धि हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि उसके प्रारंभिक आकलन के अनुसार, चार अस्पताल और एक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह नष्ट हो गया है जबकि 32 अस्पताल और 18 स्वास्थ्य केंद्र आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। भारत का एक मोबाइल अस्पताल और रूस-बेलारूस का संयुक्त अस्पताल भी अब मांडले में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहा है हैं।

मांडले में आवंटित 15 कार्यस्थलों में से 11 पर अभियान शुरू किया है और अब तक लगभग 30 शवों को निकाला है। हुसैन ने कहा, हम भारत द्वारा किए गए प्रयासों से बहुत

संतुष्ट हैं। मेरी बेटी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, उसका भारतीय सेना द्वारा स्थापित फील्ड अस्पताल में सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया है।

नेतन्याहू पहुंचे हंगरी, हंगरी ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने की योजना बनाई

» बुडापेस्ट, माषा।

हंगरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह युद्ध अपराध और जनसंहार के लिए दुनिया के एकमात्र स्थाई वैश्विक न्यायाधिकरण से हटने की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के पीछे ऑफ स्ट्राफ कोरेगेली गुलेयास ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, हंगरी अंतरराष्ट्रीय आराधिका न्यायालय से हटेगा। सरकार सदैवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे के अनुसार बृहस्पतिवार को वापसी की प्रक्रिया शुरू करेगी। यह घोषणा ऐसे समय में की गई जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेजामिन नेतन्याहू हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचे हैं।

गाजा पट्टी में युद्ध के लिए उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट



जारी है। ओरबान के नेतृत्व वाली हंगरी की सरकार ने नवंबर में नेतन्याहू को यह निमंत्रण दिया था, वहीं नीदरलैंड के हेग स्थित आईसीसी ने मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप में उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। नेतन्याहू के करीबी सहयोगी ओरबान ने गिरफ्तारी वारंट को निन्दनीय करार दिया था। नियम के अनुसार आईसीसी के सदस्य देशों को वारंट का सामना कर रहे सतिस्थों को उनकी धरती पर कदम रखने पर हिरासत में लेना होता है।